दैनिक भास्कर, पटना 15th अक्टूबर 2014

शिक्षा को ज्ञान के आधार पर ही देखें

स्कूली शिक्षा गरीबों के लिए हालात नाजुक, बच्चे स्कूलों तक नहीं पहुंच पा रहे : वृशिण पटेल

भास्कर न्यूज|पटना

एक दशक में बिहार की शिक्षा के लिए सरकार ने बहुत काम किया है। 10 वर्ष पहले जब जदयू की सरकार बनी थी, तो राज्य में सिर्फ दो लाख स्कूली शिक्षक थे। यह संख्या अब 4.25 लाख हो गई है।

प्रदेश में सिर्फ 53 हजार स्कूल थे, जो 73 हजार हो गए हैं। बंद पड़े 70 फीसदी शिक्षक ट्रेनिंग कॉलेज खुल चुके हैं। फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों के लिए हालात नाजुक बने हुए हैं। आज भी बच्चे स्कूलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये बातें देशकाल सोसायटी की ओर से होटल मौर्या में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री वृशिण पटेल ने कहीं। उन्होंने कहा कि जब तक समाज के लोग शिक्षा को हर बच्चे की जरूरत नहीं समझेंगे, पूर्ण शिक्षित समाज की कल्पना नहीं की सकती।

21वीं सदी ज्ञान की

मुख्य अतिथि आद्री के सदस्य सचिव डॉ. शैबाल गुप्ता ने 21वीं सदी को ज्ञान की सदी बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा को ज्ञान के आधार पर ही देखना चाहिए। अगर जल्द शिक्षा की परेशानियों को दूर नहीं किया गया, तो हम पिछड़ते जाएंगे।

ये भी थे मौजूद

देशकाल सोसायटी के सचिव संजय कुमार, मुख्य शोधकर्ता डॉ. मनोज कुमार तिवारी, आरती वर्मा और सत्यनारायण मदन।

होटल मौर्या में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री वृशिण पटेल व अन्य।

पढ़कर सुनाने का बच्चों का स्तर दयनीय

देशकाल सोसायटी ने गया और कटिहार जिले के एक-एक ब्लॉकों में स्कूली शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें इस बात का खुलासा होता है कि पढ़कर सुनाने का बच्चों का स्तर बहुत ही दयनीय है। चिंता की बात है कि गरीब एवं सामाजिक रूप से वंचित समुदाय के बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित हैं। गणित की स्थिति और भी खराब है।

शिक्षा के घटते स्तर के मुख्य कारण

माता-पिता की शिक्षा का स्तर, परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि एवं असहाय स्थिति, पलायन, शैक्षणिक बदलाव, निजी शिक्षण की व्यवस्था आदि।

Hindustan Times, Patna
14th October 2014

HINDUSTAN TIMES, PATNA
TUESDAY, OCTOBER 14, 2014

Patel bats for 'societal ownership' to improve school education

MINISTERSPEAK Citizens would have to rise above 'parochial thinking and be like 'tola sevak'

Arun Kumar
htpatna@hindustantimes.com

PATNA: Education minister Brishin Patel on Monday said that societal ownership was the only way that meaningful education could reach the masses without discrimination and help reduce the chasm between haves and have-nots.

"Imagine a situation in a village, in which a school is running, but right opposite, a group of children remain engrossed in playing marbles. The teachers pass that way, as do villagers. But nobody bothers to stop and tell them to go to school. Why? Because they feel the children are not theirs. Had any of the children been their, the reaction would have been different," he added.

Patel was speaking after releasing the report on 'social diversity and learning achievement', prepared by Deshkal Society after survey in two of Bihar districts — Gaya and Katihar.

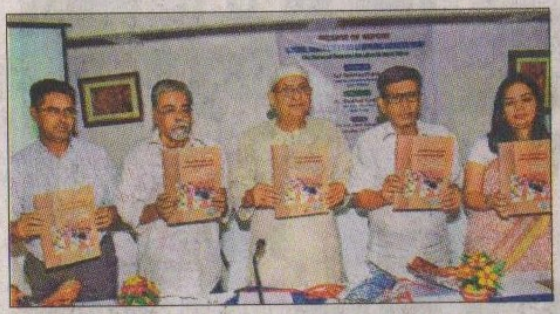

Education minister Brishin Patel (third from left) and others releasing a report in Patna on Monday. HT PHOTO

Patel said each citizen would have to rise above 'parochial thinking' and be like 'tola sevaks' (volunteers appointed by the government to encourage Mahadalits to go to school) to ensure that no child remains out of school. "If 'tola sevaks' can do, so can we. This realisation is important to usher in qualitative change in schools and make education truly inclusive," he added.

Chief minister Jitan Ram Manjhi had also recently stated on a public platform that government school teachers sent their own wards to private schools and "sit with their feet on the desk while taking classes in their own school".

Maintaining, that the number of primary schools has increased from 52,000 in 2005 to over 73,000 today, while the number of teachers has gone up from two lakh to 4.27 lakh, Patel said there was need for over two lakh more teachers to bring down the teacher: pupil ratio from 1: 49 to 1:40.

"But the point of concern is that despite doing so much, surveys indicate poor learning outcome of students. There is rush for private schools, most of which pay less than what the government pays," he added.

Patel said the government's efforts has resulted in reduction in dropout rate from 11% in 2005 to 3%, but there is need to bring all children to schools and hold them there. "It is unfortunate that in a state that was once known for institutions line Nalanda and Vikramshila, we are sliding in education. This will have to made a societal movement to link everyone with education," he added, praising Deshkal report for highlighting the socio-economic indicators

Shaibal Gupta of ADRI said that in the post independence period, a lot was done for forward linkages of education with the setting up of big institutions, which was necessary at that time, while backward linkages of education in the form of schools and literacy remained neglected.

Sanjay Kumar, secretary, Deshkal, said the report is an attempt to document the contribution of school and education system on learning outcomes of children in the light of diverse social and economic backgrounds.

MK Tewari presented the report, while Arti Verma laid emphasis on proper monitoring through a special taskforce.

हिन्दुस्तान, पटना

15 अक्टूबर 2014

निजी शिक्षण में लड़कियों से आगे हैं राज्य के लड़के

रिपोर्ट

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

- 'सामाजिक विविधता और बच्चों का शिक्षण स्तर' पर रिपोर्ट जारी
- माता-पिता की शिक्षा का असर बच्चों की शिक्षा पर

निजी शिक्षण के मामले में राज्य के लड़के लड़कियों से आगे हैं। इस मामले में अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय काफी पीछे है। प्राथमिक शिक्षा का स्तर गांवों में अच्छा नहीं है। बच्चे अंकों की गिनती तक नहीं कर पाते हैं। किताबों की रीडिंग के मामले में भी बच्चों की स्थिति अच्छी नहीं है।

'सामाजिक विविधता और बच्चों का शिक्षण स्तर' पर देशकाल सोसायटी की और सोमवार को जारी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट को शिक्षा मंत्री वृशिण पटेल ने जारी किया। रिपोर्ट गया और कटिहार जिलों में किए गए सर्वे के आधार पर जारी की गई। इसके अनुसार गया जिले में अनुसूचित जाति के सिर्फ 29.27 प्रतिशत और जनजाति के मात्र नौ प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। इसके विपरीत अगड़ी जाति के 62.03 प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों में शिक्षा पाते हैं। कटिहार में भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। इस जिले में अनुसूचित जाति के 36.31 और ऊंची जाति के 61.22 प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं।

सर्वे रिपोर्ट में माता-पिता के शिक्षित होने का असर भी बच्चों की शिक्षा पर देखा गया। गया जिले में 63 प्रतिशत माताएं कभी स्कूल नहीं गईं। ऐसे पिता की संख्या भी लगभग तीस प्रतिशत है।

कटिहार में 73 प्रतिशत माता और 52 प्रतिशत पिता कभी स्कूल नहीं गए।

प्रभात खबर, पटना (15 अक्टूबर 2014)

बढ़ी छात्रों की संख्या, गुणवत्ता पर अब भी सवाल

देशकाल ने जारी की गया और कटिहार जिले की सर्वे रिपोर्ट

संवाददाता.पटना

सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले छात्रों की संख्या बढ़ी है. दाखिले में वृद्धि का मुख्य कारण हाशिये पर रहने वाले समुदायों की पहली पीढ़ी के छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है. लेकिन, शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल अब भी कायम है. बढ़े हुए दाखिले की जरूरतों को पूरा करने के सरकारी प्रयासों के बाद भी बड़ी संख्या में प्रशिक्षित शिक्षकों एवं एवं कमरों की जरूरत है. सरकार इस कमी को पूरा नहीं कर पायी है. शिक्षा के क्षेत्र में शोध करने वाली देशकाल सोसायटी ने सोमवार को गया और कटिहार जिले का अध्ययन कर रिपोर्ट जारी की है. रिपोर्ट के अनुसार पहली कक्षा से पांचवीं में दाखिले की संख्या 2002-03 से 99,91,379 से बढ़ कर 2012-13 में 1,32,98,802 हो गयी है. रिपोर्ट में माता-पिता की शिक्षा के स्तर, आर्थिक स्थिति एवं प्राइवेट स्कूलों की कार्यप्रणाली की विस्तार से चर्चा की गयी है. रिपोर्ट के प्रधान शोधकर्ता मनोज तिवारी ने कहा कि अध्ययन में बात सामने आयी है कि जिन परिवारों के बच्चे पहली बार स्कूलों में पहुंचे हैं उन्हें पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर कोई मदद नहीं मिल पा रही है. ऐसे छात्र पूरी तरह स्कूली शिक्षा पर ही आश्रित होते हैं. वहीं हर गांव में निजी स्कूल ओर कोचिंग संस्थान खुल रहा है. जहां महादलित, अल्पसंख्यक और उंची जाति के बच्चे भी पढ़ रहे हैं. गया और कटिहार जिले में प्रारंभिक कक्षा में आये छात्रों में वैसे छात्रों की संख्या अधिक है जिनके माता पिता ने स्कूल का मुंह नहीं देखा था.

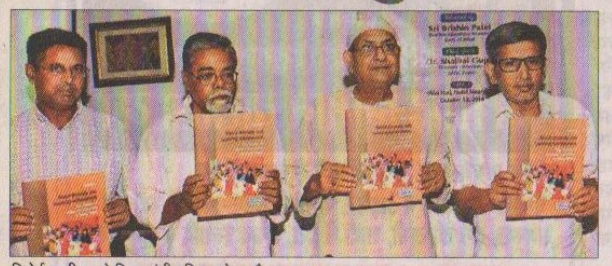

रिपोर्ट जारी करते शिक्षा मंत्री वृशिण पटेल, शैबाल गुप्ता व अन्य.

इनके कारण गुणवत्ता नहीं

- अपर्याप्त कमरे
- छात्र-शिक्षक का सही अनुपात नहीं होना
- कम शिक्षक
- शिक्षकों को दूसरे कार्यों में लगाना
- विद्यालय एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों के बीच समन्वय का अभाव
- प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी

सरकार से अनुशंसा

- बच्चों का सामाजिक परिचय तैयार कराना,पहली पीढी के छात्रों पर विशेष ध्यान देना
- अलग अलग बोली बोलने वाले छात्रों को प्रोत्साहित किया जाये
- माता-पिता को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, इसके लिए टोला सेवकों को मिले विशेष प्रशिक्षण
- मदरसों के साथ भेदभाव दूर करना

जागरूक बनें माता-पिता : शैबाल

पटना. आद्री के सदस्य सचिव शैबाल गुप्ता ने कहा है कि बच्चों में शिक्षा के लिए अभिभावक को जागरूक होना जरूरी है. वे देशकाल द्वारा सामाजिक विविधता एवं बच्चों के शिक्षण स्तर पर ग्रामीण बिहार में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति पर जारी रिपोर्ट पर बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा उसके माता-पिता की मानसिकता पर निर्भर करता है.बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता के बारे में जानकारी नहीं होती है. इसे उसके माता-पिता को ही समझना होगा. देशकाल द्वारा जारी रिपोर्ट को उन्होंने गंभीर बताया. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों स्कूली शिक्षा को नजर अंदाज करते रहे हैं. वृशिन पटेल के कार्यकाल में कई तरह के संस्थान खोले गये. राज्य में व्यापक पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हुई. शिक्षा में पब्लिक निवेश की आवश्यकता है. इसके बल पर व्यापक पैमाने पर विकास संभव है. 1980 में जापान में यह काफी बढ़ा. इसके कारण जापान लगातार नोबेल प्राइज प्राप्त कर रहे हैं. पब्लिक निवेश से संसाधन बढ़ता है. इस संसाधन का लाभ मिलता है. शिक्षा मंत्री वृशिण पटेल ने कहा कि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या घटकर अब तीन प्रतिशत तक रह गयी है. राज्य में 2005 में मात्र 52 हजार स्कूल थे. अब इसकी संख्या बढ़कर 73 हजार तक पहुंच गयी है. राज्य में शिक्षकों की संख्या 4.25 लाख हैं. शिक्षा के अधिकार कानून के तहत दो लाख और शिक्षकों की आवश्यकता है. कार्यक्रम को पीएसीएस के स्टेट मैनेजर आरती वर्मा ने भी संबोधित किया. कार्यक्रम का संचालन देशकाल सोसाइटी के सचिव संजय कुमार ने किया कि जबकि धन्यवाद ज्ञापन निदेशक सत्य नारायण मदन ने किया.

पलायन से पढ़ाई पर असर

रिपोर्ट के अनुसार गरीब परिवार के मुखिया या कमाने वाले व्यक्ति के पलायन से उनके परिवार के बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ी है. गया जिले में करीब 38 प्रतिशत मुसलमान और 35 प्रतिशत अति पिछड़ी जाति के माता-पिता अपने बच्चों को साथ लिये बगैर रोजी रोटी के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं. ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है.

The Telegraph, Patna 14th October-2014

Education support for backward classes

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

Education department minister Brishen Patel on Monday urged people from all sections of society to come forward and help increase the education level of Mahadalits and other marginalised communities.

He was speaking at a function organised by non-government organisation Deshkal Society on the occasion of releasing its report, "Social diversity and learning achievements: the status of primary education in rural Bihar".

Patel said: "In the past few years, the government has taken various initiatives to improve education in the state. This is visible in the high enrolment percentage of schoolchildren and decrease in dropout rate among students."

The number of primary schools in the state has gone up from 52,000 in 2005 to 73,000 in 2014. The number of teachers in government schools has increased from 2 lakh in 2005 from 4 lakh in 2014. The dropout rate among school students has gone down from 11 per cent in 2005 to 3 per cent in 2014.

Shaibal Gupta, member secretary, Asian Development Research Institute, who was also present on the occasion said education of a child depends mostly on the attitude of parents and atmosphere in the house. "Rabindranath Tagore had never received a formal education, but his parents' approach towards education helped him become a Nobel laureate."

Gupta also stressed the need on public investment in education, both at university and school level. "In Japan, public investment in education is very high and this is the reason why so many Japanese are receiving Nobel prizes now."

The Deshkal report is an outcome of the study taken in two districts, namely Gaya and Katihar, with the intention of tracking the present primary education system in rural Bihar.

Sanjay Kumar, secretary, Deshkal Society, said: "Gaya and Katihar were selected for data collection for the report since these two districts have high percentages of Scheduled Castes (SC) and Muslims. The SC constitutes 30 per cent of total population in Gaya, while Katihar has 42.52 per cent of Muslims. The report highlighted that children from upper castes attend private tuitions more than that of children of Scheduled Castes, Scheduled Tribes (ST) and Muslims. In Gaya, only 29.27 per cent and 9.06 per cent of SC and ST children, respectively receive private tuitions against 62.03 per cent children from upper caste. The report also highlighted the education level of parents influences the academic excellence of children."

The Times of India, Patna

14th October 2014

Minister releases report on poor edu scenario

Times News Network

Patna: Approximately 30% fathers and 63.41% of mothers in Gaya district never went to school. The situation in Katihar district is even worst with 51.58% fathers and 73.44% of mothers did not go to school. This was revealed in a report on 'social diversity and learning achievement: the status of primary education in rural Bihar' prepared by Deshkal society. The report was released by education minister Brishen Patel here on Monday.

Speaking on the occasion, he said it is difficult to teach children with lower level of parental education as they do not appreciate the value of education properly.

Pramod Sharma

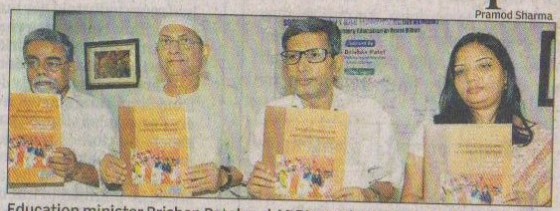

Education minister Brishen Patel and ADRI member-secretary Shaibal Gupta release report in Patna on Monday

The report was prepared after a survey on over 4,000 children in Gaya and over 5,000 children in Katihar districts. It also attributed language barrier as a factor that can increase the number of dropouts. It has mentioned private tuition centres as a single entrepreneurship in the absence of financial resource and said people accept them as centres of learning.

Noted economist Shaibal Gupta, while quoting an example of Macedonian King Alexander who was privately tutored by Aristotle, said private tuitions must not be slammed and attributed the increasing sense of completion among students to the mushrooming of private coaching centres.